



फैक्ट

इंडिया न्यूज़

FACT INDIA NEWS



RNI NO. DELHIN/2015/65319

शनिवार 02 जुलाई 2022 नई दिल्ली

■ वर्ष : 07

■ अंक : 228

■ मूल्य : 2/-

■ पृष्ठ : 08

www.factindianews.com

खबर एक नज़र

मोदी ने सफल प्रक्षेपण पर इसरो को दी बधाई



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पीएसएलवी सी 53 मिशन द्वारा अंतरिक्ष में भारतीय स्टार्ट-अप के दो पे-लोड के सफल प्रक्षेपण के लिये इन-स्पेसई और इसरो को बधाई दी है। मोदी ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा, अंतरिक्ष में भारतीय स्टार्ट-अप के दो पे-लोड को लॉन्च करके पीएसएलवी सी 53 मिशन ने एक नया पड़ाव अर्जित कर लिया है। यह कारनामा कर दिखाने के लिए इन-स्पेसई और इसरो को बधाई।

वर्तमान जीएसटी ने अर्थव्यवस्था को किया बर्बाद : पी.चिदंबरम



नई दिल्ली। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को 'एक राष्ट्र, एक कर' के सिद्धांत के साथ लागू किया गया था। शुक्रवार को इस कानून के पांच साल पूरे हो गए। इस अवसर पर कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता पी.चिदंबरम ने इस कानून की खामियों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की। यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे पी.चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस यह स्पष्ट करना चाहती है कि यह वो जीएसटी नहीं है, जिसे कांग्रेस नीत यूपीए सरकार लागू करना चाहती थी। यह जो जीएसटी है, वह त्रुटिपूर्ण, दोषपूर्ण और अस्थिर है। यह कानून इतना दोषपूर्ण है कि सरकार को सैकड़ों कार्यदेश जारी करने पड़े। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि इस जीएसटी पर पुनर्विचार हो, ताकि देश को एक सही जीएसटी मिल सके।

जुलाई में सामान्य रहेगी वर्षा : मौसम विभाग



नई दिल्ली। मौसम विभाग ने उत्तरी, मध्य भारत और

दक्षिणी प्रायद्वीप में जुलाई में 'सामान्य और सामान्य से अधिक' बारिश होने का अनुमान जताया है। विभाग ने एक बुलेटिन में कहा कि देश में जुलाई में बारिश सामान्य रहेगी (लंबी अवधि के औसत की 94 से 106) प्रतिशत रहेगी। विभाग ने कहा, हिमालय की तलहटी और प्रायद्वीप को छोड़कर देश के अधिकतर भाग में अधिकतम तापमान सामान्य या सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। हिमालय की तलहटी और प्रायद्वीप में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने के आसार हैं।

केरल में माकपा के एकेजी सेंटर पर हमला

तिरुवनंतपुरम। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के यहां स्थित पार्टी मुख्यालय एकेजी सेंटर पर अज्ञात हमलावरों ने बम फेंका। करीब 23.45 बजे स्कूटर पर आए दो लोगों में एक ने कार्यालय के मुख्य द्वार पर बम फेंका। हमले में किसी के घायल होने की रिपोर्ट नहीं है। घटना के दौरान कई माकपा नेता कार्यालय में मौजूद थे। विस्फोट की तेज आवाज सुनकर इलाके में इयूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और पार्टी के लोग मौके पर पहुंचे।

पैगंबर पर विवादित बयान से सुप्रीम कोर्ट सर्रत , कहा

नूपुर को देश से मांगनी चाहिए माफी



नई दिल्ली, 1 जुलाई (एजेंसियां)। पैगंबर पर विवादित बयान देने के लिए नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि नूपुर ने टेलीविजन पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की। उन्होंने अपने बयान से लोगों की भावनाएं भड़काई हैं और देशभर में जो कुछ भी हो रहा है, उसकी जिम्मेदार नूपुर ही हैं। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। कोर्ट ने कहा कि अपने बयान पर माफी भी उन्होंने शर्तों के साथ ही मांगी, वह भी तब, जब लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। यह उनकी जिद और घमंड दिखाता है। कोर्ट ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे एक पार्टी की प्रवक्ता हैं। वे सोचती हैं कि उनके पास सत्ता का समर्थन है और वे कानून के खिलाफ जाकर कुछ भी बोल सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आपके लिए यहां रेड कारपेट होना चाहिए। जब आप किसी के खिलाफ शिकायत करती हैं, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। आपके दबदबे की वजह से कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं। आप सोचती हैं कि आपके पास सत्ता का समर्थन है और आप कानून के खिलाफ जाकर कुछ भी बोल सकती हैं। नूपुर के वकील ने कहा नूपुर को धमकियां मिल रही हैं। कोर्ट ने कहा नूपुर को धमकियां मिल रही हैं। या वे खुद सुरक्षा के लिए खतरा हैं? देश में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए वही जिम्मेदार हैं। पैगंबर के खिलाफ नूपुर शर्मा की टिप्पणी या तो सस्ते प्रचार, राजनीतिक एजेंडे या कुछ नापाक गतिविधियों के लिए की गई थी। ये धार्मिक लोग नहीं हैं और भड़काने के लिए ही बयान देते हैं।

नूपुर शर्मा पर न्यायालय की टिप्पणी वापस लेने की अर्जी

भाजपा की निर्बाचित प्रवक्ता नूपुर शर्मा पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ की मौखिक टिप्पणियां हटाए जाने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक याचिका दाखिल की गई। गौ महासभा के अध्यक्ष अजय गौतम ने नूपुर के वकील ने कहा नूपुर को धमकियां मिल रही हैं। कोर्ट ने कहा नूपुर को धमकियां मिल रही हैं। या वे खुद सुरक्षा के लिए खतरा हैं? देश में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए वही जिम्मेदार हैं। पैगंबर के खिलाफ नूपुर शर्मा की टिप्पणी या तो सस्ते प्रचार, राजनीतिक एजेंडे या कुछ नापाक गतिविधियों के लिए की गई थी। ये धार्मिक लोग नहीं हैं और भड़काने के लिए ही बयान देते हैं।

ऐसे लोग दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करते। हमने देखा है कि बहस के दौरान नूपुर ने कैसे उकसाने वाली बात कही, उसके बाद भी वे कहती हैं कि मैं एक वकील हूं। यह शर्मनाक है। नूपुर को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। यह याचिका आपके घमंड को दिखाती है। आप लोअर कोर्ट की जगह

- देशभर में जो कुछ भी हो रहा है, उसके लिए नूपुर को ठहराया गिम्मेदार
- कोर्ट ने माना, नूपुर ने टेलीविजन पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की
- अपने बयान पर माफी भी शर्तों के साथ ही मांगी वह भी तब जब लोगों का गुस्सा भड़क चुका था

टीवी चैनल व दिल्ली पुलिस को भी लगाई फटकार

कोर्ट ने विवादित बहस को दिखाने वाले टीवी चैनल और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा, दिल्ली पुलिस ने क्या किया? हमें मुंह खोलने पर मजबूर मत कीजिए। टीवी डिबेट किस बारे में थी? इससे केवल एक एजेंडा सेट किया जा रहा था। उन्होंने ऐसा मुद्दा क्यों चुना, जिस पर अदालत में केस चल रहा है।

सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। देशभर के मजिस्ट्रेट कोर्ट आपके लिए छोटे हैं।

नूपुर की याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर के खिलाफ देश के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे मामलों को

देश के शीर्ष न्यायालय ने जो बातें भाजपा की पूर्व को लेकर कही हैं

उससे भाजपा को उसका असली चेहरा दिखाया गया है। भाजपा को इस दर्पण में अपना चेहरा देखना चाहिए और फिर शर्म से अपना सिर झुका लेना चाहिए : **जयराम रमेश**

नूपुर शर्मा मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी सांप्रदायिक ताकतों के लिए है सबक : मायावती

दिल्ली ट्रांसफर करने की उनकी याचिका भी खारिज कर दी। कोर्ट की फटकार के बाद नूपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि वे अपने बयान पर माफी मांग चुकी हैं और उन्होंने इसे वापस भी ले लिया है।

इस पर कोर्ट ने कहा कि जब माफी मांगी गई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद उनके वकील ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी, कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में दो जजों ने ने 27 मिनट की सुनवाई के बाद कुल तीन लाइन के आदेश में नूपुर की याचिका का निपटारा कर दिया। हालांकि बेंच ने नूपुर पर जो चार सबसे तलख टिप्पणियां की थीं, उनका जिक्र कोर्ट के आदेश में नहीं था।

कोर्ट ने उदयपुर हत्याकांड का जिक्र किया

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुबह ग्यारह बजकर तीन मिनट पर सुनवाई शुरू हुई, जो साढ़े ग्यारह बजे तक चली। कुल 27 मिनट की सुनवाई में कोर्ट ने उदयपुर हत्याकांड का जिक्र भी किया।

शिंदे के सामने सत्ता बचाने की चुनौती

शिंदे की अयोग्यता पर 11 जुलाई को विचार करेगा सर्वोच्च न्यायालय

मुंबई, 1 जुलाई (एजेंसियां)। महाराष्ट्र में भाजपा के समर्थन से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन सरकार बचाना शिंदे के लिए भी आसान नहीं है। कानूनी रूप से देखा जाए, तो महाराष्ट्र की सरकार एडहॉक पर है, जो बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत पर टिकी है।

इस बीच, शिवसेना के चीफ व्हिप ने नई अर्जी दायर करके सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि 16 बागी विधायकों को वोट देने से रोका जाए। हालांकि इस पर भी 11 जुलाई को ही सुनवाई होनी है।

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत 16 विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर अंतिम निर्णय आने तक उन्हें निर्बाचित करने तथा विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेने का निर्देश देने की मांग संबंधी शिवसेना की याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई



बागी अयोग्य घोषित हुए तो पलट सकता है पासा

करेगा।

उद्धव ठाकरे कैप को फिर से लगा झटका

सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के उद्धव ठाकरे कैप को फिर से झटका लगा है। अदालत ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि 11 जुलाई को ही अन्य केंसों

यदि अमित शाह बाईं साल पहले बात मान लेते तो महाविकास अघाड़ी का गठन ही नहीं होता और अब 2.5 साल के लिए महाराष्ट्र में भाजपा का सीएम होता : उद्धव ठाकरे

के साथ ही इस मसले पर सुनवाई की जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उन 15 बागी विधायकों को विधानसभा से निर्बाचित किए जाने का अनुरोध करने वाली शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु की याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं। 16 बागी विधायकों की संख्याता रद्द करने और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला सुप्रीम कोर्ट में है।

मणिपुर भूस्खलन में 82 लोग दबे

इंफाल, 1 जुलाई (एजेंसियां)। मणिपुर के नोनी जिले में टैरिटेरियल आर्मी के जवानों समेत अभी भी 44 लोग मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। गुरुवार को जवानों का कैप लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया था। जिसके बाद से एनडीआरएफ की टीम बड़े पैमाने पर रेस्क्यू मिशन चला रही है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक, 18 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया



- 15 जवानों व 5 नागरिकों के शव निकाले गए
- 18 लोगों को बचाया गया 44 की तलाश जारी

है, जबकि 15 जवानों और 5 नागरिकों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। घायलों को इलाज के लिए नोनी आर्मी मेडिकल यूनिट लाया गया है।

देश की रक्षा को लेकर बड़ा कदम

भारत के घातक ड्रोन का सफल परीक्षण

नई दिल्ली, 1 जुलाई (एजेंसियां)। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने पहली बार ऑटोनॉमस फ्लाईंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर को उड़ाया। यह उड़ान कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई। अमेरिका के बी-2 बमवर्षक की तरह दिखने वाला ये विमान पूरी तरह से स्वचालित था। इसने खुद ही टेक ऑफ लिया, वे प्वाइंट नैविगेशन और आसानी से लैंडिंग की। यह उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की



राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को दी बधाई

दिशा में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को साबित करने के मामले में एक प्रमुख उपलब्धि है। यह देश की रक्षा को लेकर भी बड़ा कदम है। इसे बेंगलुरु स्थित एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टैबलिशमेंट ने बनाया

स्वायत्त विमानों की दिशा में यह बड़ी उपलब्धि : राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई देते हुए कहा कि यह स्वायत्त विमानों की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। इससे महत्वपूर्ण सैन्य प्रणालियों के रूप में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

है। यह एक छोटे टर्बोफैन इंजन से उड़ता है।

कन्हैयाला हत्याकांड मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर, 1 जुलाई (एजेंसियां)। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त महानिदेशक अशोक राठौड़ ने बताया कि उदयपुर नृशंस हत्याकांड मामले में गुरुवार देर रात दो बजे इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों आरोपियों को रैकी एवं आपराधिक षडयंत्र रचने के मामले में गिरफ्तार किया गया।

राठौड़ ने बताया कि इन दोनों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया गया। उन्होंने बताया कि इससे पहले इस मामले के दो मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अख्तारी एवं गौस मोहम्मद को गत 28 जून को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था और इनकी शिनाख्त परेड के लिए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेकर अजमेर की हाई सिक्स्योरिटी जेल भेजा गया है।



अभियान

जम्मू कश्मीर में कचरा मुक्त तीर्थयात्रा अभियान शुरू

अमरनाथ यात्रा में निकलने वाले कचरे का होगा इस्तेमाल

जम्मू, 1 जुलाई (एजेंसियां)। अमरनाथ यात्रा को जीरो वेस्ट बनाने की मुहीम का असर दिखाई देने लगा है। जम्मू कश्मीर के रूरल डेवलपमेंट विभाग ने कचरा मुक्त तीर्थयात्रा अभियान शुरू किया है। स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर कचरा मुक्त तीर्थयात्रा का काम चल रहा है। यात्रियों को प्लास्टिक और पालिथीन ले जाने से रोका जा रहा है। इसके अलावा यात्रा मार्ग में कचरे को उठाने और उसके निपटान की पूरी मशीनरी लगाई गई है।

पहले दो दिन से ही इस अभियान का असर दिखाई दे रहा है। लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। इस काम में सहयोगी स्टार्टअप 'स्वाहा' के वालंटियर्स लगे हुए हैं। इस योजना का लक्ष्य पहाड़ों और नदियों को प्रदूषण से मुक्त रखना है। प्रतिवर्ष अमरनाथ यात्रा में 500 टन कचरा निकलता रहा है। इस बार करीब 800 टन कचरा निकलने का अनुमान है। इस अनूठी योजना के बारे में आईएसएस अधिकारी और सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर मनदीप कौर का कहना है कि इस वर्ष केंद्र

- पहाड़ों व ग्लेशियर को बचाना अभियान का उद्देश्य
- प्रतिवर्ष अमरनाथ यात्रा में निकलता है पांच सौ टन कचरा

सरकार के मार्गदर्शन 'स्वच्छ भारत अभियान' और यूएनीपी की ओनली वन अर्थ को गाइड लाईंस मानते हुए यह तय किया गया कि अमरनाथ के निवास और पवित्र गुफा दर्शन के इस आयोजन को पूर्णतः सस्टेनेबल और कचरा मुक्त रखा जाए। इसका उद्देश्य



प्रकृति, पहाड़ों, ग्लेशियर्स की रक्षा के साथ-साथ इस यात्रा को एक मिसाल बनाना है। यात्रियों को जागरूक करने के लिए कुछ नारे भी बनाए हैं। ये हैं 'प्रभु का घर गन्दा नहीं करेंगे हम', 'यश शिव ओंकारा, मिठायेगे कचरा

सारा'। डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट और सेनिटेशन चरुणजीत सिंह ने बताया कि यात्रा की पूरी तरह से सिंगल यूज पालीथीन और डिस्पोजल प्लास्टिक से मुक्त रखने को हम प्रतिबद्ध हैं। यात्रा मार्ग में चलने वाले लंगरों के प्रबंधन को जागरूक किया जाएगा। उनके सहयोग से अमरनाथ का धाम पूरी तरह कचरा मुक्त करने पर जोर है। इस योजना के सहयोगी स्वाहा संस्था के को-फाउंडर समीर शर्मा का कहना है कि किसी भी तरह का वेस्ट लैंडफिल में नहीं जाने दिया जाएगा। कचरे को

रीसायकल किया जाएगा। कचरे से बनी खरब किसानों और इलाके की नगर परिषद के काम आएगी। इसके लिए स्पॉट पर ही सेग्रिगेशन और प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई हैं। कचरे के मार्ग में चलने वाले लंगरों के उपयोग पर भी काम हो रहा है। यात्रा मार्ग पर सोलर कान्स्ट्रैटर लगाए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट विभाग इसके जरिए यात्रा को हर दृष्टि से प्रदूषण मुक्त बनाने में जुटा है। ये सोलर कान्स्ट्रैटर दूध, पानी गर्म करने, चावल, मैगी, आलू उबालने में काम आएंगे।



दिल्ली में एसयूपी वस्तुओं पर प्रतिबंध के उल्लंघन पर एक लाख तक का जुर्माना या जेल की सजा : राय

नई दिल्ली, 1 जुलाई (एजेंसियां)। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि शुक्रवार से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, पहले चरण में प्रतिबंध के दायरे में 19 वस्तुओं को शामिल किया गया है। दिल्ली सरकार ने इसके लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। एक तरफ जहां सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प को बढ़ावा देने के लिए तमाम कदम उठा रही है। वहीं दूसरी तरफ इसके प्रतिबंध को लागू करने के लिए डीपीसीसी तथा राजस्व विभाग द्वारा एनफोर्समेंट टीम का गठन किया है।

जिसमें डीपीसीसी की 15 और राजस्व विभाग की 33 टीम एसयूपी वस्तुओं पर प्रतिबन्ध का निरिक्षण करने का कार्य करेंगी। इसके तहत 10 जुलाई तक एसयूपी प्रतिबन्ध का उल्लंघन करने वालों को चेतावनी नोटिस जारी किए जाएंगे और उसके बाद उनके खिलाफ इन टीमों के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही एसयूपी वस्तुओं पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या 5 साल तक की जेल की सजा भी होगी।

दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक के

- दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने त्यागराज स्टेडियम में किया प्लास्टिक विकल्प मेले का उद्घाटन
- एसयूपी वस्तुओं पर लगाए प्रतिबन्ध पर निरिक्षण के लिए 48 टीमों का किया गया गठन: गोपाल राय



विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार को त्यागराज स्टेडियम में शुरू किया गया प्लास्टिक विकल्प मेला। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा शुक्रवार को इस प्लास्टिक विकल्प मेले का उद्घाटन किया गया। यह मेला त्यागराज स्टेडियम में 3 जुलाई तक लग रहा है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों पर काम कर रही कम्पनियां, स्टार्ट अप्स और उत्पादक अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई हुई है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबन्ध को लागू करने के साथ साथ लोगों में एसयूपी के विकल्पों के लिए जागरूकता अधियान शुरू करना है।

दिल्ली बनी प्रदूषण के खिलाफ फाउंटेन सिटी नंबर वन: गोपाल राय

प्लास्टिक विकल्प मेले में आए बच्चों और दर्शकों को संबोधित करते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली को प्रदूषण के खिलाफ में भारत में नंबर वन शहर बनाने के लिए चौबीसों घंटे कार्यरत है। ऐसे में देखा गया है कि प्रदूषण को बढ़ावा देने में सिंगल यूज प्लास्टिक भी एक एहम भूमिका निभाता है और आज से जब पुरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 वस्तुओं पर बैन लगाया गया है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार एसयूपी वस्तुओं पर बैन

लगाने के लिए टू लाइन एक्शन प्लान पर कार्य कर रही है - 'एनफोर्समेंट के साथ समाधान'। दिल्ली सरकार ने आज से इस प्लास्टिक विकल्प मेले को शुरुआत की है ताकि लोगों को एसयूपी वस्तुओं से सम्बंधित प्रतिबन्ध से पहले उनके विकल्पों के बारे में भी जानकारी दी जा सके।

कल आयोजित किया जाएगा राउंड टेबल कॉफ़ेंस

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि यह तीन दिवसीय मेला सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य विकल्पों को उत्पादन करने वाली कंपनी, स्टार्ट अप्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक प्लेटफॉर्म देने के साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य ईको फ्रेंडली विकल्पों को बढ़ावा देने का कार्य भी करेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य विकल्पों के बारे में और जानकारी लोगों के बीच साझा हो सके इसलिए 3 जुलाई को सभी स्टॉक होल्डर के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। साथ ही जो भी लोग सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी सरकार इस मेले में नई ग्रीन स्टार्टअप पॉलिसी ला रही है ताकि वह सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्य विकल्पों के व्यवसाय में जुड़ सकें और सरकार इसके लिए उनको सहायता भी प्रदान करेगी।

सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद दिल्ली के प्रदूषण में आएगी कमी :आदेश गुप्ता



द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाए जाने के बाद केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली की जनता को इसके विकल्प के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग मार्केट में समान खरीदने के लिए जा रहे हैं लेकिन प्लास्टिक की जगह केजरीवाल सरकार द्वारा कोई विकल्प दुकानदारों को अभी तक न देने से उन्हें बिना समान लिए वापस आना पड़ रहा है। व्यापारी परेशान हैं कि उन्हें इन आइटमों के विकल्प महंगे तो मिल ही रहे हैं लेकिन डिमांड के अनुरूप भी नहीं मिल रहे हैं। अभी

सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के मद्देनजर निगम ने जब्त की प्लास्टिक

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के मद्देनजर गुरुवार को 689.01 किलो प्लास्टिक की वस्तुओं को जब्त किया और 368 किलोना किए। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन वस्तुओं में प्लास्टिक की छड़ें, गुब्बारा के लिए प्लास्टिक की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की छड़ें, आइसक्रीम की छड़ें, सजावट के लिए पॉलीस्टायरीन, प्लेट, कप, गिलास, कांटे की चम्मच, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, रिंग या मिठाई के बक्कों पर पैकेजिंग फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेटों, 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पीवीसी बैनरों और स्टिटर शामिल हैं। निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार प्रतिबंधित वस्तुओं के भंडारण, बिक्री और उपयोग को समाप्त करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कुल 125 प्रवर्तन दल गठित किए गए हैं। दिल्ली नगर निगम प्रतिबंध को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है।

व्यापारी जितना ऑर्डर करते हैं उसका सिर्फ 20 फीसदी भी ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण है कि प्लास्टिक की जगहों पर जो विकल्प उपलब्ध है उनका चेन सिस्टम सही नहीं है और वे

महंगे भी हैं। ऐसे में आने वाले समय में आम जनता के ऊपर इसका भी बोझ बढ़ने वाला है। प्लास्टिक के विकल्पों की कालाबाजारी भी शुरू हो चुकी है जिससे चीजें और महंगी होंगी।

इस्तेमाल किए जा चुके तेल का होगा उचित निपटारा

नई दिल्ली, 1 जुलाई (एजेंसियां)। शेल ने यूज्ड ऑयल मैनेजमेंट सर्विस की शुरुआत की। यह भारत में इस्तेमाल किए जा चुके तेल के निपटारे की प्रणाली को व्यवस्थित बनाने और रि-फ़ाइनरिंग की दर को बढ़ाने का एक नया प्रयास है, ताकि कचरे को कम करते हुए सर्कुलर इकोनॉमी के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। इस मौके पर मानसी त्रिपाठी, वाइस प्रेसिडेंट, शेल लुब्रिकेंट्स एशिया पैसिफिक ने कहा की हम भारत में उद्योग के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ-साथ कचरे को कम करने की प्रक्रिया को किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा लक्ष्य लुब्रिकेंट्स में सर्कुलर इकोनॉमी को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाने और इस सेवा के लिए वृद्धि की संभावनाएं तलाशना है, ताकि कचरे को कम किया जा सके और इस तरह कुल उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सके।

देबांजलि सेनुगुप्ता, कंट्री हेड, शेल लुब्रिकेंट्स इंडिया ने कहा, सॉल्यूशन आधारित ग्राहक केंद्रित संगठन होना हमारे कारोबारी मॉडल का मुख्य उद्देश्य है। यह प्रयास उन्हीं मूल्यों को दोहराता है और इससे हमें अपने ग्राहकों को लुब्रिकेंट्स से आगे बढ़कर व्यापक सेवाएं उपलब्ध करारक उन्हें सहायता देने में मदद मिलेगी। यह तथ्य और भी महत्वपूर्ण है कि अब हमारे पास सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ने की दिशा में पहला कदम बढ़ाने का अवसर है।

को लॉन्च करने की बेहद खुशी है। कस्टमर-फर्स्ट ब्रांड के रूप में, हमारा मानना ​​है कि बाजार में लगातार विस्तार और निवेश से यह ब्रांड संरक्षकों के लिए और अधिक सुलभ बन सकेगा।

इस सीजन को अनोखे अंदाज में मनाते हुए, कल्याण ज्वैलर्स ने देश भर के ग्राहकों के लिए एक अनूठी पेशकश की है। इस बम्पर ऑफर के तहत, कल्याण ज्वैलर्स भारत के अपने किसी भी शोरूम में खरीदे गये प्रत्येक 10 ग्राम के गोल्ड ज्वेलरी पर आधा ग्राम सोना देंगे। ग्राहक 10 ग्राम से कम के आभूषणों की खरीद पर उनके मेकिंग चार्ज पर और 15 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाकर अपने आभूषणों की खरीद पर तत्काल बचत कर सकते हैं, जो चुनिंदा आभूषणों पर लागू है।



हुए, कल्याण ज्वैलर्स के पंजाब की क्षेत्रीय ब्रांड एंबेसडर वामिका गब्बी ने कहा की कल्याण ज्वैलर्स भारत के सबसे प्रतिष्ठित आभूषण ब्रांडों में से एक है और ऐसी कंपनी का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात है जो आभूषण उद्योग में

पारदर्शिता और नैतिक व्यवसाय पद्धतियों का नेतृत्व कर रही है। रमेश कल्याणरामन, कार्यकारी निदेशक कल्याण ज्वैलर्स ने कहा की यहां कमला नगर में हमारी 158वीं वैश्विक आउटलेट और दिल्ली एनसीआर में 11वीं प्रोजेक्ट



दिल्ली देश के सबसे पुराने होलसेल मार्केटों का हब है और ये मार्केट दिल्ली को एक पहचान देते हैं। साथ ही बड़ी आबादी को रोजगार प्रदान करने वाली दिल्ली की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं: मनीष सिसोदिया

फेस्टिवल के आयोजन व मार्केटिंग के माध्यम से इनकी पहुंच को बढ़ाने और उन्हें दूरदराज के उपभोक्ताओं की पहुंच के भीतर ले जाने में मदद करेंगे।

इच्छुक थोक विक्रेताओं को रियायती दरों पर उपलब्ध करवाई जाएगी जगह

सिसोदिया ने आगे कहा कि दिल्ली के होलसेल मार्केटों में देश भर के व्यवसायों और खरीददारों को

आकर्षित करने के लिए 10-14 दिन के लिए होलसेल शापिंग फेस्टिवल का आयोजन होगा। एक्सपों में भाग लेने के इच्छुक सभी थोक विक्रेताओं को रियायती दरों पर जगह उपलब्ध करवाई जाएगी। थोक विक्रेताओं के व्यापार को बढ़ावा देने और दिल्ली को थोक और व्यापार का केंद्र बनाने के इरादे से, होलसेल मार्केट एक्सपों महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा।

बिक्री पर टैक्स रिफंड और छूट सहित दिए जाएंगे इन्स्टैंटिव

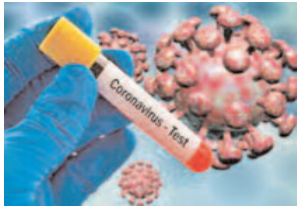
एक्सपों में भाग लेने के लिए सभी प्रमुख होलसेल मार्केटों को आमंत्रित किया जाएगा। खरीदारों को आकर्षित करने और थोक विक्रेताओं के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भारत और दुनिया भर में बड़े स्तर पर विज्ञापन व मार्केटिंग कैम्पेन चलाए जाएंगे। एक्सपों के दौरान होने वाली बिक्री पर टैक्स रिफंड और छूट सहित कई तरह के इन्स्टैंटिव दिए जाएंगे और दिल्ली में थोक विक्रेताओं से खरीदारी के लिए इसे आकर्षक बनाने के लिए अन्य वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

दिल्ली में घटी कोरोना संक्रमण दर, 3 ने तोड़ा दम

नई दिल्ली, 1 जुलाई (एजेंसियां)। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर तेजी से घट रही है। राहत की बात यह है की संक्रमित के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शुक्रवार को कोरोना के 813 नए मामले सामने आए, वहीं 1021 मरीजों को छुट्टी दी गई। जबकि 3 मरीज ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया है। दिल्ली

24 घंटे में 813 नए मामले

में कोरोना की जांच 2672 मरीज होम के लिए 15339 टेस्ट हुए जिसमें 5,30 फीसदी लोग संक्रमित पाए गए। दिल्ली में अभी तक 1935687 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1905720 मरीज ठीक हो गए हैं जबकि 26264 मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। दिल्ली



में कोरोना से मृत्युदर 1.36 फीसदी है। विभाग के अनुसार दिल्ली में घटते कोरोना के मामलों के साथ एक्टिव की संख्या 3703 रह गई है। इनमें से 2672 मरीज होम आईसोलेशन में जबकि 218 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से 79 आईसीयू में, 70 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर और 7 मरीज वेंटिलेटर पर भर्ती हैं। दिल्ली में घटते मामलों के साथ हॉस्पिटल की संख्या घटक 386 रह गई है।

प्रथम गोरखा मेजर दुर्गा मल्ल शहीद की 109 वीं जयंती

अब्दुल कलाम/संवाददाता फैक्ट इंडिया न्यूज़ नई दिल्ली, 1 जुलाई आजाद हिन्द फौज के प्रथम गोरखा सैनिक अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की आज 109 वीं जयंती है। जंग ए आजादी के इस सूरमा ने आजाद हिन्द फौज में रहते हुए ब्रितानिया हुकूमत से लोहा लिया और उनके दांत खट्टे कर दिए। जिसके बलिदान की वीरगाथा और शौर्य से पूरा नॉर्थ ईस्ट ही नही बल्कि पूर्वोत्तर भारत के लोग आज भी गौरवान्वित महसूस करते है।

शहीद मेजर दुर्गा मल्ल ने अपना बलिदान देकर उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश का गौरव बढ़ाया। अपने प्राणों का बलिदान देकर उन्होंने आजादी के संघर्ष को धार दी। भारत की स्वतंत्रता के लिए युवावस्था से ही आंदोलनों में भाग लेकर संघर्ष करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों के आगे सीना तानकर उन्होंने आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। जंग ए आजादी के संघर्ष में मेजर शहीद दुर्गामल्ल ने निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने युवाओं को आजादी के संघर्ष से जोड़ने का काम किया। शहीद दुर्गा मल्ल की देशप्रेम की भावना को युवाओं को आत्मसात करना चाहिए। रिजवान रजा बताते है कि शहीद मेजर दुर्गा मल्ल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर सिंगापूर में आजाद हिन्द फौज का गठन किया। जिसमें दुर्गा मल्ल की बहुत सहायनी भूमिका रही। इसके लिए मल्ल को मेजर के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होंने युवाओं को आजाद हिन्द फौज में शामिल करने में बड़ा योगदान दिया। दुर्गा मल्ल को युद्धबंदी बनाने और मुकदमे के बाद उन्हें बहुत यातना दी गई। 15 अगस्त 1944 को उन्हें लाल किले की सेंट्रल जेल लाया गया और जहाँ 25 अगस्त 1944 को उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। 17 जुलाई 2004 में संसद परिसर में शहीद दुर्गा मल्ल की प्रतिमा लगाई गई।

छात्रों के लिए देशभक्ति, उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम मूल्यांकन केनए मानदंड

एजेंसी ■ नई दिल्ली

दिल्ली सरकार के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में स्कूली छात्रों का अब अन्य शैक्षिक विषयों के साथ-साथ उनके व्यवहार में मानसिकता पाठ्यक्रम के प्रभाव के लिए मूल्यांकन किया जाएगा। शिक्षा निदेशालय के नए दिशानिर्देशों के मुताबिक, तीसरी से आठवीं कक्षा तक के छात्रों का मूल्यांकन हैपिनेस और देशभक्ति पाठ्यक्रमों के लिए किया जाएगा, जबकि नौवीं से 11वीं कक्षा तक के छात्रों का मूल्यांकन देशभक्ति उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के लिए किया जाएगा। हालांकि 11वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के लिए

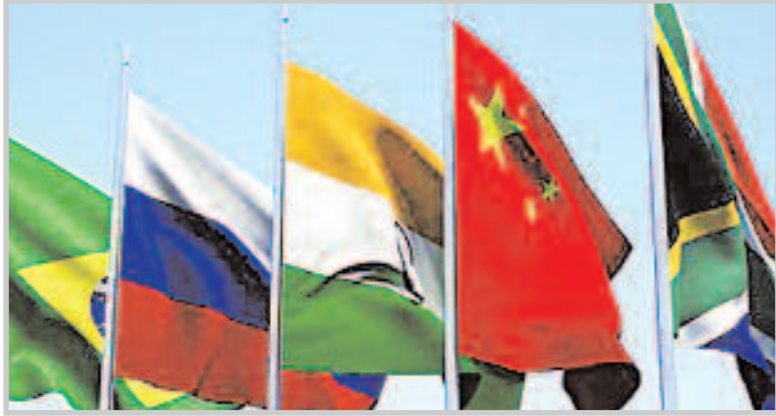
एक अतिरिक्त मानदंड होगा जो बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम में उनकी भागीदारी से संबद्ध होगी। बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम के तहत छात्रों को मुनाफा देने वाला एक विचार प्रस्तुत करने या किसी सामाजिक समस्या का हल करने के लिए 2,000 रुपए की शुरुआती रकम मुहैया की जाती है। नए मानदंड पहले से मौजूद मूल्यांकन नियमों के एक पूरक का काम करेंगे और वे सह-पाठ्यक्रम अकादमिक गतिविधियों पर आधारित होंगे। सिसोदिया ने कहा, हमने मूल्यांकन मानदंड में संशोधन किया है और आगे बढ़ रहे हैं, छात्रों का मूल्यांकन मुख्य पाठ्यक्रमों के उनके ज्ञान के अतिरिक्त उनकी क्षमताओं के आधार पर किया।





दखल

ब्रिक्स के भीतरी विरोधाभास



ब्रिक्स के गठन की नींव बीस साल पहले पड़ी थी। तब इसके पीछे मकसद अमेरिकी आर्थिक ढांचे से हट कर एक वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना था। यह विचार अच्छा था, पर इस पर ढंग से काम नहीं हो पाया। 2009 के बाद से ब्रिक्स के औचित्य पर ही सवाल खड़े किए जाने लगे। अब यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। चीन भारत पर इस बात के लिए दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि वह यूक्रेन के मुद्दे पर रूस और चीन के साथ खड़ा हो।

हाल में ब्रिक्स देशों की 14वीं शिखर बैठक में सदस्य देशों ने अलग-अलग बातें कहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निशाना साधा और रूस पर आर्थिक प्रतिबंध थोपने की निंदा की। साथ उन्होंने मौजूदा वैश्विक आर्थिक संकट के लिए इन देशों को दोषी ठहराया। दूसरी तरफ सकारात्मक पहलू को रेखांकित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक व्यवस्था को बेहतर और लोकतांत्रिक बनाने पर जोर दिया और महामारी से निपटने के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था को भी अपने भाषण का हिस्सा बनाया। जबकि चीन ने दुनिया को शीत युद्ध से बचने की नसीहत दी। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील ने भी महामारी और उससे निपटने में ब्रिक्स के योगदान का जिक्र किया। इससे यह साफ हो गया कि ब्रिक्स के सदस्य देशों की प्राथमिकताएं क्या हैं। अगर संक्षेप में ब्रिक्स की सार्थकता और गतिशीलता को देखा जाए तो कई विसंगतियां और विरोधाभास सामने आते दिखाई देते हैं। भारत और चीन के बीच जिस तरह का गतिरोध बना हुआ है और भारत को लेकर चीन का जो आक्रामक रुख कायम है, उससे ब्रिक्स की एकता कहीं न कहीं प्रभावित होती है। ताजा विवादों को लेकर चीन अपनी जिद पर अड़ा है। भारत ने 1950 से लेकर 2019 तक चीन की हर मुसीबत में साथ दिया। इसके बावजूद चीन की नजर में भारत एक सहयोगी नहीं, बल्कि विरोधी है, इस सोच ने दोनों देशों के बीच तल्छी पैदा कर दी। आज भारत को ब्रिक्स और पश्चिमी कूटनीति के बीच जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, वैसी स्थिति पहले शायद ही कभी बनी हो। लेकिन जिस कुशलता के साथ भारत ने क्राइ और ब्रिक्स में संतुलन साधा है, वह विदेश नीति के मोर्चे पर कम बड़ी बात नहीं है। जर्मनी में जी-7 देशों की बैठक में भी ब्रिक्स के दो सदस्य भारत और दक्षिण अफ्रीका मौजूद हैं। यह भी कि यूक्रेन युद्ध के मसले पर संयुक्त राष्ट्र में तटस्थ नीति छोड़ने भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका पर दबाव भी बनेगा। जबकि भारत बात स्पष्ट कर चुका है। ब्रिक्स की प्रासंगिकता का को लेकर भी सवाल उठ ही रहे हैं। दरअसल चीन ब्रिक्स का विस्तार करने की कोशिश में लगा है। ब्रिक्स प्लस बनाने के पीछे चीन की योजना यही है कि वह अमेरिकी और पश्चिमी ताकतों के समतार नया समूह खड़ा कर सके। लेकिन उसकी यह कोशिश क्या सिरि चढ़ पाएगी, यह बड़ा सवाल है। अगर ब्रिक्स का विस्तार होता है तो भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की

क्या भूमिका होगी, यह स्पष्ट नहीं है। गौरतलब है कि भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड समूह का भी महत्वपूर्ण सदस्य है। ब्रिक्स के गठन की नींव 20 साल पहले पड़ी थी। तब इसके पीछे मकसद अमेरिकी जनित आर्थिक ढांचे से हट कर एक वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना था। यह विचार अच्छा था, पर इस पर ढंग से काम नहीं हो पाया। इसलिए 2009 के बाद से ब्रिक्स के औचित्य पर ही सवाल खड़े किए जाने लगे। अब इस बात की आशंकाएं गहरी जा रही हैं कि कहीं ब्रिक्स के विस्तार की आड़ में इसके विघटन की शुरुआत न होने लगे। इसके कारण है। पहला कारण यह कि ब्रिक्स का विस्तार चीन अपने नक्शे कदम पर करना चाहता है। उसकी कोशिश जी-20 संगठन से कुछ देशों को ब्रिक्स में शामिल करने की है। इसमें इंडोनेशिया भी है। गौरतलब है कि इंडोनेशिया को लेकर भारत के रिश्ते अच्छे हैं। चीन अफ्रीका के दो महत्वपूर्ण देशों-नाइजीरिया और सेनेगल को भी ब्रिक्स में शामिल करने की कोशिश करेगा। इनके शामिल होते ही संगठन में दक्षिण अफ्रीका की अहमियत घटने लगेगी। दक्षिण अफ्रीका की सहमति के बिना इनको खेमे में लेना ब्रिक्स के विघटन का कारण बन सकता है। इसी तरह अर्जेंटीना के ब्राजील से अच्छे रिश्ते नहीं हैं। अगर ब्राजील की सहमति के बिना अर्जेंटीना को ब्रिक्स में लिया गया तो यह भी कम पेचीदा स्थिति नहीं होगी। चीन की सूची में कई और भी देश हैं। चीन की पूरी कोशिश एक ऐसा नया खेमा खड़ने की है जो अमेरिका और उसके वर्चस्व वाले खेमे को चुनौती दे सके। दूसरा कारण यह है कि ब्रिक्स का आर्थिक आधार अभी भी बहुत कमजोर है। अभी पांचों देशों की कुल आबादी तकरीबन दुनिया की 40 फीसद के करीब है। पांचों देशों की जीडीपी वैश्विक जीडीपी का एक चौथाई है। 25 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था 18 लाख करोड़ तो केवल चीन का हिस्सा है, जबकि भारत साढ़े तीन लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। बाकी तीन देशों की स्थिति बेहद नाजुक है। वैश्विक महामारी में ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका काफी पीछे रह गए हैं। ब्रिक्स का आपसी व्यापार मुश्किल से बीस फीसद रह गया है। ऐसे हालात में इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि ब्रिक्स यूरोपियन महासंघ या जी-7 की बराबरी कर पाएगा? तीसरी वजह यूक्रेन युद्ध ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। एक बार फिर से दुनिया दो खेमों में बंट गई है। नए शीत युद्ध का आगाज होता दिख रहा है। यूक्रेन युद्ध के कारण

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के दामों में भारी इजाफा हुआ है। दरअसल चीन इस युद्ध को लेकर अपनी चौकड़ी बनाने की कवायद में लगा है। सैन्य रूप से मजबूत रूस आर्थिक रूप से पूरी तरह से कमजोर पड़ता जा रहा है। युद्ध ने उसकी हालत और जर्जर बना दी है। इसलिए चीन रूस को लेकर एक ऐसा गुट बनाना चाहता है जो दुनिया का मठाधीश बनने के उसके सपने को पूरा कर सके। इसके लिए वह ताइवान पर हमले का पता भी चलने को तैयार दिखता है। चौथा कारण यह कि चीन तेजी से विस्तारवादी नीति पर चल रहा है। श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया, आस्ट्रेलिया और कई अफ्रीकी देश चीन की इस कुटिलता का दंश झेल रहे हैं। जहां तक सवाल है भारत का, तो भारत और चीन के बीच दो साल से गंभीर टकराव चल रहा है। हालांकि चीन इसे गंभीर सीमा विवाद के रूप में नहीं देख रहा, पर भारत के लिए यह बेहद नाजुक मसला बन गया है। भारत ने साफ कर दिया है कि विवादित स्थलों से पहले चीनी सेना की वापसी हो तभी और बातचीत संभव होगी। चीन ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से वैश्विक व्यवस्था को अपने तरीके से संचालित करने की साजिश रची है, उससे दुनिया के तमाम देशों का चिंतित होना स्वाभाविक है। दुनिया के सामने कभी भी इतना डर और संशय नहीं रहा जितना कि आज इस बात को लेकर है कि चीन दुनिया का मुखिया बन गया तो क्या होगा? अब यूक्रेन युद्ध की वजह से वैश्विक राजनीति के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। चीन भारत पर इस बात के लिए दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि वह यूक्रेन के मुद्दे पर रूस और चीन के साथ खड़ा हो। लेकिन भारत जिस तरह से तटस्थता की नीति पर चल रहा है, उसमें यह आसान नहीं है। ऐसे में अगर ब्रिक्स में चीन और रूस के दबाव में कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो दूसरे सदस्यों की सोच सके विपरीत होंगे, तो इससे ब्रिक्स में एक तरह की फूट पड़ सकती है। भारतीय प्रासंगिकता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। अभी दुनियाभर के प्रमुख देशों की नजर भारत पर टिकी है। भारतीय कूटनीति के लिए यह भी अग्निपरीक्षा का समय है। हालांकि, भारत ने शुरू से साफ कर दिया है कि यूक्रेन के मुद्दे पर उसकी विदेश नीति तटस्थता की है और रहेगी। ब्रिक्स में चीन जिस तरह के दांव चल रहा है, उससे निपटने सभी देशों को आगे आना होगा और कवायद करनी होगी।

फ़ैक्ट संवाद

उद्धव को भाजपा का जोर का झटका

शिंदे के साथ शिवसेना के 39 विधायकों की बगावत के बाद से उद्धव खेमा भाजपा को विलेन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा था। विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाना शुरू कर दिया था। भाजपा ने एक झटके में इसे ध्वस्त कर दिया है।



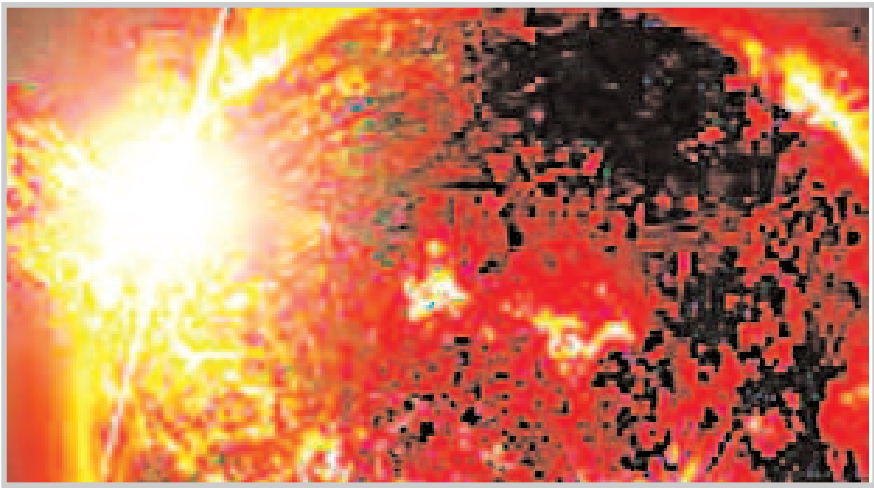
भाजपा की मौजूदा लीडरशिप को चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाना जाता है। ऐसा ही निर्णय महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी एकनाथ शिंदे को देकर लिया गया है। शिंदे कैप की शिवसेना से बगावत से लेकर अब तक यही माना जा रहा था कि उनके समर्थन से भाजपा सरकार बनाएगी और कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथों में होगी। लेकिन अब एकनाथ को महाराष्ट्र का नाथ बनाकर भाजपा ने मास्टरस्ट्रोक चल दिया है, जिसका अनुमान किसी भी राजनीतिक पंडित ने नहीं लगाया था। भाजपा को इस त्याग का बड़ा फल आने वाले वक्त में मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को करारा झटका लग सकता है। कहा जा रहा है कि भाजपा ने इस दांव के जरिए उद्धव ठाकरे से सत्ता छीनने के बाद पार्टी और बालासाहेब की विरासत से भी उन्हें बेदखल करने की कोशिश की है। दरअसल उद्धव ठाकरे लगातार इमोशनल कार्ड खेल रहे थे और खुद को बालासाहेब की विरासत का असली वारिस बता रहे थे। यही नहीं उनका कहना था कि भले ही सरकार वो लोग बना लें, लेकिन मेरे पास शिवसेना रहेगी।

ऐसे में भाजपा ने शिवसेना के ही बागी एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया है ताकि पार्टी के ज्यादातर लोग प्रभावित होकर शिंदे के खेमे में आ जाएं। ऐसा होता है तो शिवसेना बेहद कमजोर होगी और दो धड़ों में बंटी पार्टी आने वाले वक्त में चुनौती नहीं दे पाएगी। इसके अलावा अपने फायदे को लेकर भी शायद भाजपा ने यह फैसला लिया है। दरअसल 2019 में भी अजीत पवार को साथ लेकर फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ले ली थी, लेकिन 80 घंटे तक ही सत्ता में रह पाए थे। ऐसे में अब एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर भाजपा ने यह साबित कर दिया कि वह सत्ता की लालची नहीं है। दूसरा किंगमेकर बनकर वह सत्ता का संचालन भी कर सकेगी। दरअसल शिवसेना एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद से ही मराठी कार्ड चल रही थी। उसका कहना था कि हम महाराष्ट्र के लोगों की पार्टी हैं और भाजपा कभी किसी शिवसैनिक को सत्ता में नहीं आने देगी। लेकिन भाजपा ने इस दांव को चलकर उसके दोनों दांवों की काट कर दी है। इसके जरिए भाजपा मराठा बेल्ट में अपनी दावेदारी ठोक सकेगी और बालासाहेब की विरासत की सच्ची वारिस होने का भी दावा करेगी। बता दें कि बिहार में भाजपा ने ऐसा ही किया था, जब 2020 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर जीत के बाद भी नीतीश कुमार को ही सरकार बनाने का मौका दे दिया था। जानकारों का यह भी कहना है कि फडणवीस ने लंबी छलांग लेने के लिए कुछ कदम पीछे लिए हैं। वह इस कदम से जनता को यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि उसने शिवसेना की सरकार गिराई नहीं है, बल्कि हिंदुत्व के अजेंडे से हट चुके उद्धव गुट को हटाकर बालासाहेब ठाकरे के नक्शेकदम पर आगे बढ़ने वाली शिवसेना को सत्ता में आने में मदद की है। अगले चुनाव में भाजपा को इसका लाभ मिल सकता है।

आग उगलते सूरज को देख कर तो लगता है कि ताप युग की शुरुआत हो गई है। पिछले एक दशक से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसके लिए सूर्य में हो रहे ताप संबंधी बदलाव जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक चेतानियों से स्पष्ट है कि प्रकृति के साथ मानवता के पुराने मैत्रीपूर्ण रिश्तों में दरार आ गई है। आज प्रकृति और विश्व शांति दोनों ही खतरे में हैं। बढ़ता वैश्विक तापमान (ग्लोबल वार्मिंग) और परमाणु परीक्षणों व युद्धों से उत्पन्न होने वाले विकिरण आज मानव अस्तित्व के लिए कहीं ज्यादा बड़े खतरे बन गए हैं। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी व्यापक और शक्तिशाली होती जा रही है। यह सिलसिला आने वाले दशकों में भी जारी रहेगा। सूचना और संचार क्रांति ने भी अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। लेकिन यह भी ब्रह्मांडीय खतरों से मुक्त नहीं है। अंतरिक्ष से भी सूरज से आने वाले विकिरण इसे प्रभावित करते हैं। इसलिए अब वैज्ञानिक शोध हो रहे हैं कि कैसे सूर्य के विकिरणों से बचा जा सके।

वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में एक विशालकाय बुलबुले का निर्माण करके सूरज से आने वाले खतरनाक विकिरणों को धरती पर पहुंचने से रोका जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे विनाश को रोकने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने सूर्य और पृथ्वी के बीच अंतरिक्षीय बुलबुला यानी 'स्पेस बबल' बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह बुलबुला ब्राजील के आकार का होगा। इसका नाम 'इम्प्लेमेंटेबल बबल' होगा। इसे तरल सिलिकान से बनाया जाएगा और सूरज तथा पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। सूरज से आने वाले खतरनाक विकिरण इस बुलबुले से टकरा कर परावर्तित हो जाएंगे और धरती तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर यह प्रयोग कामयाब हो गया, जैसा कि वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं, तो धरती के लिए यह एक बड़ा सुखसा कवच साबित होगा।

हालांकि सूरज से आने वाले विकिरणों को इस बुलबुले के जरिए भी रोक पाना संभव नहीं होगा, पर इसे कम जरूर किया जा सकेगा। अंतरिक्ष बुलबुला शोध परियोजना वैज्ञानिक जेम्स अर्ली के विचारों पर आधारित है जिन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष में एक विश्वेपी वस्तु तैयार करने का सुझाव दिया था। फिर खगोलविद रोजर एंजेल ने बबल-बेड़े का प्रस्ताव रखा। हालांकि जियो-इंजीनियरिंग एक विज्ञान कथा से कम नहीं लगती, लेकिन इसका इस्तेमाल वास्तविक दुनिया में सफलतापूर्वक हो रहा है। वैसे तो धरती का चुंबकीय क्षेत्र ही हमें सूरज से आने वाले विकिरणों से बचाता है, लेकिन सूरज



ऐसी संभावना है कि अंतरिक्ष में जहां जेम्स वेब टेलीस्कोप स्थित है, वहां इस अंतरिक्ष बुलबुले को रखा जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज से आने वाले विकिरणों को परावर्तित करने के लिए यही सबसे सही जगह होगी। जो भी हो, वैज्ञानिकों का यह कदम सराहनीय है क्योंकि धरती बचाओ की मुहिम अंतरिक्ष से भी होनी चाहिए। सौर तूफान को लेकर वैज्ञानिकों की खोज वृहद होनी चाहिए।

पर उठने वाले तूफानों का असर धरती पर काफी पड़ता है। सूरज पर अनवरत उठते रहने वाले सौर तूफानों के मुकाबले अब भविष्य के सौर तूफानों की तीव्रता ज्यादा भयावह होगी जो अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे उपग्रहों को प्रभावित करेंगे और हमारी संचार व्यवस्था व जीपीएस प्रणाली को उप कर सकते हैं। आसमान से सूरज तो आग उगल ही रहा है, पराबैंगनी किरणें भी अब एक खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका स्तर औसत से तीन गुना और बढ़ गया है जो मनुष्य के लिए खतरनाक साबित होगा। ऐसे में कड़ी धूप में बाहर निकलने वालों की आंखों में जलन, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर और अन्य बीमारियां होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से सूर्य पर हलचल भरी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। पिछले दिनों सूरज पर मौजूद एक धब्बे में भयानक विस्फोट की तस्वीरें सामने आईं। इस विस्फोट को पृथ्वी के लिए खतरे

इसके अलावा कम तीव्रता का एक सौर तूफान 1989 में भी आया था। माना जा रहा है कि पिछले तूफानों के मुकाबले अब भविष्य के सौर तूफानों की तीव्रता ज्यादा भयावह होगी जो अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे उपग्रहों को प्रभावित करेंगे और हमारी संचार व्यवस्था व जीपीएस प्रणाली को उप कर सकते हैं। आसमान से सूरज तो आग उगल ही रहा है, पराबैंगनी किरणें भी अब एक खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका स्तर औसत से तीन गुना और बढ़ गया है जो मनुष्य के लिए खतरनाक साबित होगा। ऐसे में कड़ी धूप में बाहर निकलने वालों की आंखों में जलन, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर और अन्य बीमारियां होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से सूर्य पर हलचल भरी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। पिछले दिनों सूरज पर मौजूद एक धब्बे में भयानक विस्फोट की तस्वीरें सामने आईं। इस विस्फोट को पृथ्वी के लिए खतरे

के रूप में देखा जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस विस्फोट से निकलने वाले विकिरण धरती पर भू-चुंबकीय तूफान का कारण बन सकते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के खराब होने का खतरा और बढ़ जाता है। भू-चुंबकीय तूफान एक प्रकार का सौर तूफान है जो पूरे सीस्मंडल को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यह धरती के चुंबकीय क्षेत्र पर असर करने वाली आपदा है। इस साल की शुरुआत में एलन मस्क की स्पेस कंपनी के चालीस उ पग्रह भू-चुंबकीय तूफान के शिकार हो गए थे। अंतरिक्ष मौसम के बारे में शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि 2020 से ही सौर-तूफान चक्र की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले दिनों में पृथ्वी पर ऐसे ही कई सौर तूफान देखने को मिलेंगे।

सौर तूफान के दौरान सूरज की सतह से 'ऊर्जा का गुब्बारा' फूटता है। इससे पृथ्वी पर विद्युत आवेश और चुंबकीय क्षेत्र की खेप आती रहती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सूरज पर लंबे समय तक ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली थी, लेकिन अब चक्र एक बार फिर शुरू हो चुका है। पृथ्वी पर ऐसे सौर तूफान की वजह से पावर ग्रिड और संचार व्यवस्था पर तो असर पड़ता ही है, प्राणियों के लिए भी यह खतरनाक है। इस तरह के सौर तूफान इंसानों पर घातक प्रभाव डालते हैं। सौर तूफान को लेकर वैज्ञानिकों की खोज भी सीमित रही है। पहले इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था। लेकिन हाल के वर्षों में कई देश अंतरिक्ष मौसम के बारे में ज्यादा गंभीर हुए हैं। भारतीय वैज्ञानिक भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं।

वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज से आने वाले विकिरणों को इस अंतरिक्ष बुलबुले की तकनीक से पूरी तरह तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं कि यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के मौजूदा प्रयासों का विकल्प होगा। हां, यह बात जरूर है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए जो भी मौजूदा उपाए किए जा रहे हैं, उनमें यह सबसे ज्यादा कारगर होगा। अंतरिक्ष में इस बुलबुले का परीक्षण भी किया जा चुका है और आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया जाएगा। यदि हम धरती पर ठकाने से पहले ही 1.8 प्रतिशत सौर विकिरण को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देंगे तो बढ़ते वैश्विक तापमान की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकेंगे। इस बुलबुले की खूबी यह है कि अगर खराबी आ जाए तो बदला भी जा सकता है।

बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं

लगातार बनाए हुए हैं। अपने क्षेत्र की जनता के साथ वह लगातार संपर्क में रहते हैं। जनता से उनका रिश्ता ऐसा है कि लोग उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह जानते हैं। केवल रहली विधानसभा क्षेत्र या सागर जिला ही नहीं, मध्यप्रदेश के किसी भी जिले से कोई पार्टी कार्यकर्ता या आम आदमी उनके पास पहुंचता तो तो वह जो मदद हो सकती है उसके लिए तत्काल कार्यवाही करते हैं। श्री भार्गव का जन्म 1 जुलाई 1952 को रहली में हुआ वह छत्र जीवन से ही सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। वर्ष 1970 में वे छत्र राजनीति के दौरान छत्र संघ में पदाधिकारी बने। सागर विश्वविद्यालय में



छत्र संघ में महत्वपूर्ण पदों पर चुने गए। इसके बाद रहली के नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर रहते हुए उन्होंने अपने सेवा कार्यों को आगे बढ़ाया। वर्ष 1984 में रहली विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। उन्हें वर्ष 2003 में मुख्यमंत्री उमा भारती ने कैबिनेट मंत्री बनाया। वह बाबूलाल गौर के मुख्यमंत्री काल में भी कैबिनेट मंत्री रहे। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी दी है। श्री भार्गव वर्तमान में लोक निर्माण विभाग, खादी ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग के मंत्री हैं। उन्होंने प्रदेश के दूरदराज के दुर्गम क्षेत्रों को सड़क से जोड़ने का प्रभावी कार्य किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश में 2 हजार 441 किलोमीटर नवीन सड़कें और 65 नए पुल बनाने

का कार्य तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के महानगरों में रेल पटरी के कारण बाधित हो रहे यातायात को सुगम बनाने के लिए 105 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण भी प्रस्तावित है। इससे श्रम और समय की बचत होगी। आवागमन की सुविधा बढ़ेगी। मध्यप्रदेश में अटल प्रोग्रेस वे और नर्मदा एक्सप्रेस वे की महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है जिससे प्रदेश का अन्य राज्यों से सड़क संपर्क अधिक बेहतर हो जाएगा। इसी प्रकार खादी ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग में भी नई-नई योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। हथकरघा मध्यप्रदेश की समृद्ध और ऐतिहासिक धरोहर है।

■ अभिताम पांडेय

यूक्रेन ने यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए किए हस्ताक्षर

कोव, 1 जुलाई (एजेंसियां)। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने पार्लियामेंट के अध्यक्ष रुस्लान स्टोफनचुक और प्रधानमंत्री डेनिस शमीहाल के साथ शुक्रवार को यूरोपीय संघ (ईयू) का पूर्ण सदस्य बनने के लिए अपनी एकजुटता साबित करने के लिए संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए।

श्री जेलेंस्की ने अपने टेलीग्राम एकाउंट पर कहा, आज हम यूरोपीय संघ में पूर्ण सदस्यता के एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, जो सरकार की सभी मंत्रालयों की एकता का संकेत है और यूक्रेन के रणनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के हमारे दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। इस बयान पर हस्ताक्षर करने का मतलब प्रवेश के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर करना है जैसे युद्ध के पांचवें दिन। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सदस्यता के लिए 'जल्दी' का रास्ता तय करना होगा।



यूक्रेन के ओडेसा पर रूसी मिसाइल हमले में 18 लोगों की मौत

कोव। यूक्रेन के अधिकारियों ने शुक्रवार को दावा किया कि ओडेसा में एक अपार्टमेंट की इमारत तथा एक मनोरंजन केंद्र पर तीन रूसी मिसाइलों के हमले में दो बच्चों सहित 18 लोगों की मौत हो गई और अन्य 31 लोग घायल हो गए हैं। ओडेसा क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन के गवर्नर और प्रमुख मैक्सिम मार्चेनको ने टेलीग्राम पर कहा, ओडेसा क्षेत्र के बेलगोरोड-डेनिएस्टर जिले में काला सागर से टीयू-22 सामरिक विमान द्वारा रात मिसाइल हमला हुआ। तीन एक्स-22 मिसाइलों को एक अपार्टमेंट की इमारत तथा एक मनोरंजन केंद्र पर दागा गया। उन्होंने कहा कि सुबह नौ बजे तक, दो बच्चों सहित 18 पीड़ितों की पहचान हुई है तथा घायल चार बच्चों और एक गर्भवती महिला सहित 31 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अन्य आठ को चिकित्सा सहायता दी गयी।

- रूस यूक्रेन के ईयू में शामिल होने का कर रहा है विरोध
- हमें जल्द से जल्दी हासिल करनी होगी ईयू की सदस्यता : जेलेंस्की

राष्ट्रपति ने कहा, हम 115 दिनों से सदस्यता पाने की ओर जा रहे हैं और सदस्यता पाने के लिए हमारे इस रास्ते में वर्षों या दशकों का समय नहीं लगना चाहिए। हमें इसे जल्द से जल्द पाना होगा। यह किस हद तक संभव है यह हम पर निर्भर है। हमें अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम देना होगा ताकि यूरोपीय संघ में हमारे मित्र हमारे लिए एक और ऐतिहासिक निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। प्रधानमंत्री श्री शमीहाल ने ट्वीट किया कि यूक्रेन यूरोपीय संघ का पूर्ण सदस्य बनने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा, हम यूरोपीय संघ के ऐतिहासिक फैसले के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। गौरतलब है कि गत 23 जून को ब्रसेल्स में शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के नेताओं ने चर्चा के बाद यूक्रेन और मोल्दोवा को सदस्य देश का दर्जा देने के लिए मतदान कराया था।

भारत की मदद से बंदरगाह विकसित करेगा श्रीलंका

कोलंबो, 1 जुलाई (एजेंसियां)। श्रीलंका भारत की ओर से दिये गये चार करोड़ डॉलर के ऋण का उपयोग द्वीप राष्ट्र के उत्तरी छोर के कंकासंथुरई बंदरगाह को विकसित करने के लिए तैयार है। शुक्रवार को यह जानकारी दी गयी। आज जारी रिपोर्ट में कहा गया कि बन्दरगाह, जहाजरानी और परिवहन मंत्री निमल सिरिपाला डी सिल्वा ने डेली मिरर को बताया कि श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण (एसएलपीए) ने प्रारंभिक कार्य शुरू कर लिया है और बाकी का काम भारत के एक्जिम बैंक से पैसा मिलने के बाद किया जाएगा। मंत्री ने कहा, कुछ काम जो हमें करना था कर दिया, अब भारतीय की ओर से एक सलाहकार नियुक्त किया है। रिपोर्ट मिलने के बाद हम बंदरगाह के विकास के काम की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल यहां केवल छोटे जहाज ही रुक सकते हैं। हम इसे बड़े जहाजों को समायोजित किये जाने लायक विकसित करेंगे। इससे पहले मत्स्य पालन मंत्री डगलस देवानाते ने कहा था कि भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच माल वाहन शीघ्र ही शुरू होगा। भारतीय की मदद से इस बंदरगाह को विकसित करने का काम लम्बे समय से विचाराधीन था और भारत ने मई 2009 में संघर्ष समाप्ति के बाद वित्तीय सहायता की पेशकश की थी और इसके बाद वहां से मलबा आदि हटाने जैसे काम किये गये। श्रीलंका के उत्तरी हिस्से और भारत के दक्षिण हिस्से के बीच समुद्र की एक संकरी पट्टी है जो दोनो देशों को अलग करती है।

पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर

इस्लामाबाद, 1 जुलाई (एजेंसियां)। पाकिस्तान में मुद्रास्फीति जून में बढ़कर 21.32 प्रतिशत हो गई जो 13 पिछले वर्षों में सबसे अधिक है। पाकिस्तान सांख्यिकी ब्यूरो (पीबीएस) द्वारा शुक्रवार को साझा किए गए आंकड़ों से इस बात का खुलासा हुआ है। समाचारपत्र 'डॉन' के मुताबिक पिछले महीने महंगाई 13.76 फीसदी दर्ज की गई थी। जून में मुद्रास्फीति 6.34 फीसदी मासिक (एमओएम) और 21.32 फीसदी सालाना (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ी, जो दिसंबर 2008 के बाद से उच्चतम आंकड़ा था। दिसंबर 2008 में मुद्रास्फीति 23.3 फीसदी थी।



21.32 प्रतिशत हो गई महंगाई दर

पीबीएस के मुताबिक शहरी इलाकों में महंगाई 19.84 फीसदी और ग्रामीण इलाकों में 23.55 फीसदी बढ़ी है। कई क्षेत्रों में दोहरे अंकों में मुद्रास्फीति देखी गई, लेकिन प्रवृत्ति मुख्य रूप से परिवहन द्वारा संचालित थी, जो मई में 62.17 प्रतिशत की वृद्धि और खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की कीमतों में 36.34 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। शिक्षा और संचार केवल दो क्षेत्र ऐसे थे जहां मुद्रास्फीति क्रमशः 9.46 प्रतिशत और 1.96 फीसदी पर एकल अंकों में थी। पीबीएस प्रेस वक्तव्य गैर-खाद्य-संबंधित वस्तुओं में वृद्धि का विवरण देते हुए यह दर्शाता है कि मोटर ईंधन, तरलीकृत हाइड्रोकार्बन और बिजली शुल्क में साल-दर-साल भारी वृद्धि हुई है। साथ ही मोटर ईंधन की कीमतों में कम से कम 95 फीसदी की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने पहले भविष्यवाणी की थी कि आगामी वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति 15 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी।

देखी गई। शिक्षा और संचार केवल दो क्षेत्र ऐसे थे जहां मुद्रास्फीति क्रमशः 9.46 प्रतिशत और 1.96 फीसदी पर एकल अंकों में थी। पीबीएस प्रेस वक्तव्य गैर-खाद्य-संबंधित वस्तुओं में वृद्धि का विवरण देते हुए यह दर्शाता है कि मोटर ईंधन, तरलीकृत हाइड्रोकार्बन और बिजली शुल्क में साल-दर-साल भारी वृद्धि हुई है। साथ ही मोटर ईंधन की कीमतों में कम से कम 95 फीसदी की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने पहले भविष्यवाणी की थी कि आगामी वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति 15 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी।

चिंता

इस्लामाबाद 01 जुलाई (वार्ता) पाकिस्तानी संसद ने कहा कि पाकिस्तान में ब्रिटेन, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब सहित कई देशों से भारी मात्रा में खतरनाक कचरे का आयात कर रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, केवल ब्रिटेन ने पिछले साल पाकिस्तान में लगभग 40,000 टन कचरा फेंका, जिसमें नियमित और खतरनाक कचरे को अलग करने की क्षमता नहीं है, जिससे गंभीर पर्यावरण तथा स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं।

ईरान और यूएई से भी आ रहा है कचरा

इसी तरह, 25,000 टन ऐसा ही कचरा ईरान से और करीब 20,000 टन यूएई से आया है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वरिष्ठ संयुक्त सचिव सैयद मुजतबा हुसैन ने समिति के सदस्यों को जानकारी दी। जलवायु परिवर्तन पर सीनेट की स्थायी समिति ने राष्ट्रीय खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2022 पर चर्चा के लिए बैठक की, जिसमें कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ पाकिस्तान की प्रतिबद्धता के साथ साथ अन्य चीजें भी शामिल हैं। संघीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को आम सहमति से नीति को मंजूरी दी। समिति को सूचित किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे सहित अधिकांश कचरे का उपयोग

देश विदेश

पीटीआई ने लाहौर उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

इस्लामाबाद, 1 जुलाई (एजेंसियां)। पाकिस्तान तहरीक-ए-इसाफ (पीटीआई) ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता हमजा शाहबाज को पंजाब का मुख्यमंत्री चुने जाने के संबंध में लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) के फैसले को शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। 'एक्सप्रेस ट्रिब्यून' ने यह रिपोर्ट दी है रिपोर्ट के अनुसार पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में पंजाब विधानसभा के उपाध्यक्ष सरदार दोस्त मुहम्मद मजारी, श्री शहबाज और अन्य को पक्षकार बनाया है।

उन्होंने अपील में कहा कि लाहौर उच्च न्यायालय ने पार्टी की स्थिति को स्वीकार कर लिया, लेकिन अल्प सूचना पर प्रांतीय विधानसभा की बैठक बुलाने का आदेश हानिकारक होगा। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश 'असंवैधानिक' है, बैठक बुलाने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए जिससे शुक्रवार को



- पीटीआई ने शाहबाज को मुख्यमंत्री पद से निलम्बित करने की मांग की
- पंजाब में जल्द कराएं जाएं निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव

दोबारा होने वाली मतगणना में सभी सदस्य शामिल हो सके। पीटीआई ने श्री शाहबाज को मुख्यमंत्री पद से निलंबित करने और 'निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव' कराने का आह्वान किया है। उसने चुनाव पर रोक अंकट के आधार पर उसकी अपील पर सुनवाई करने का आग्रह किया है।

अमेरिकी शेयरों का 1970 के बाद से सबसे खराब प्रदर्शन



अमेरिका, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इस साल की शुरुआत में मंदी की चपेट में आ जाएगा क्योंकि ब्याज दरों में वृद्धि जारी है। हेंग सेंग बैंक चाइना के मुख्य अर्थशास्त्री डैन वांग ने बीबीसी को बताया, अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व दरों में बढ़ोतरी जारी रखता है तो शेयर बाजार काफी नकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। एएमपी कैपिटल के शेन ओलिवर ने कहा, शेयरों में निरंतर अल्पकालिक अस्थिरता देखने

की संभावना है क्योंकि केंद्रीय बैंक उच्च मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कड़े हैं, यूक्रेन में युद्ध जारी है और मंदी की आशंका अधिक है। एक अन्य प्रमुख अमेरिकी स्टॉक इंडेक्स डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इस वर्ष की पहली छमाही में 15 प्रतिशत से अधिक गिर गया जो वर्ष 1962 के बाद की अवधि में सबसे बड़ी गिरावट है। उसी समय प्रौद्योगिकी-केंद्रित नैस्डैक कंपोजिट में लगभग 30 प्रतिशत की गिरावट आई जो वर्ष की पहली छमाही के लिए इसकी सबसे बड़ी प्रतिशत गिरावट है। पिछले महीने फेड ने लगभग 30 वर्षों में अपनी सबसे बड़ी दर वृद्धि की घोषणा की क्योंकि उसने बढ़ती उपभोक्ता कीमतों पर लगाम लगाने के लिए अपनी लड़ाई तेज कर दी है।

फिजी में कोविड सुरक्षा उपाय और सख्त किए गए

सुवा, 1 जुलाई (एजेंसियां) फिजी में हाल ही में कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के नये मामलों में वृद्धि के मद्देनजर शुक्रवार को द्वीप राष्ट्र में फिर से कोविड-19 सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू किया गया है।

फिजी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (एफबीसी) ने शुक्रवार को बताया कि देश के सभी अस्पतालों को कोरोना वायरस को लेकर और अधिक सख्त सुरक्षा उपायों को फिर से लागू करने को कहा गया है। कार्यस्थलों में भी कोविड-19 सुरक्षा उपायों को अधिक सख्त करने का आग्रह किया गया है।

फिजी के स्वास्थ्य सचिव जेम्स फोंग ने बताया कि देश के अस्पतालों को आगंतुकों के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा, मास्क तथा हाथ धोने और स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल को और अधिक सख्ती से लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यस्थलों पर प्रबंधकों को कोविड के एहतियाती उपाय और अधिक सख्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

श्री फोंग ने देश में कोविड मामलों में वृद्धि की पुष्टि की हैं। श्री फोंग के अनुसार फिजी में मंगलवार से कोविड संक्रमण के 158 नए मामले दर्ज किए गए हैं।



रोसाइक्लिंग उद्योग द्वारा किया जाता है, जो पूरे देश में कराची, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला और खैबर पख्तूनख्वा में फैला हुआ है। रोसाइक्लिंग उद्योग इससे सोना, तांबा और एल्यूमीनियम जैसी धातुओं को निकालता है। पाकिस्तान में अपना कचरा फेंकने वाले अन्य देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, जर्मनी, स्पेन, कनाडा, इटली और

अन्य शामिल हैं। इस संबंध में, समिति को बताया गया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने से पहले पाकिस्तान में आयातित ठोस कचरे के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। हालांकि, एनओसी जारी करने से पहले जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रांतीय पर्यावरण संरक्षण एजेंसियों पर निर्भर था।



फैक्ट इंडिया न्यूज़

सुडोकू 5885

		3	2	4			
1				6		5	9
8	6						
2		3			1	4	
			1	6			8
						2	7
6	2			3			5
			7		9	3	

: नियम :

- कुल 81 (9×9) वर्ग हैं, जिसमें 9 (3×3) वर्गों का एक खंड (ब्लॉक) बनता है।
- हर खाली वर्ग में 1 से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते हैं।
- बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे के प्रत्येक कॉलम,कतार और खंड में 1 से 9 अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते हैं।

वर्ग पहेली 5885

१	२			३		४	
			५				
६				७			८
			९				
	१०		११			१२	
				१३			
१४		१५			१६	१७	
			१८		१९		
२०					२१		२२
		२३					

बायेंसे बायें-

- बड़ी मुश्किल से
- बाकायदा
- दहाड़
- बेइज्जत, अपमानित
- प्रयासत
- सामयिक
- जिसके अधिकार को समाप्त कर दिया गया हो (उर्दू)
- जहरीला
- छोटी टेकरी
- गंध जो का जन्मस्थल (उर्दू)
- जमीन मेंगड़बना (उर्दू)
- जुटिपूरी (उर्दू)
- प्रायः, अधिकतर
- पथ प्रशंस्क (उर्दू)
- मानव खोपड़ी

ऊपर से नीचे:-

- थोड़ा
- लिपिबद्ध (उर्दू)
- गणेश
- दरिद्री, पशु (उर्दू)
- बीता हुआ समय
- लोचदार होने का भाव
- बेरोजगार (उर्दू)
- पूर्ति होना, खर्च होना
- अवसाद, उदासी
- कल्याण, शुभ
- समान
- चौकाना, सतर्क
- छल, धोखा, लुभावना (उर्दू)
- ज्योतिषी, गिनने वाला
- बहने के गुण, पदार्थ, द्रव
- लड़ाई, युद्ध

वर्ग पहेली-5884 का हल

	२			३		४	
क	ठ	मु	ल्ला		त	ल	ह
र		स्ट	ख	स	म	त्था	
६				७			८
त	ला	क	री		क	वि	रा
ल		वि	द	शां	ना		टि
	१०	ल	११	ना		१२	
	सु		झ		१३	उ	त्प
	ल		डु		नि	ह	त्था
१४		१५				१६	१७
ब	ह	क	ना		मं		न
ल		र		१८	म	न	
२०			वे		२१		जुं
शा	र	दा	ग		व	र्ण	मा
	२३						ला
टी		ता	ज	म	ह	ल	जुं

युसूफ कुरैशी,

दुनिया को जानें

हांगकांग चीन को सौंपे जाने के 25 साल पूरे

बीजिंग 1 जुलाई (ए जें ' सिय ां) । हांगकांग को अंग्रेजों द्वारा चीन को वापस सौंपे जाने के शुक्रवार को 25 साल पूरे हो गये। ब्रिटेन ने 1997 में आज के दिन हांगकांग चीन को वापस सौंपा था।

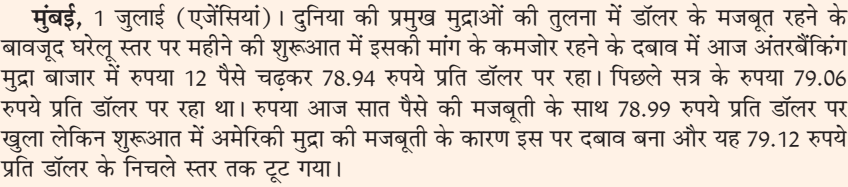
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अभी हांगकांग की यात्रा पर हैं। उनकी जनवरी 2020 के बाद से देश से बाहर यह पहली यात्रा है। इससे पहले वह 2017 में 20वीं वर्षगांठ के के मौके पर हांगकांग



गये थे। इस मौके पर आज हांगकांग में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है तथा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। समारोह आमतौर पर विक्टोरिया हार्बर पर आतिशबाजी के प्रदर्शन के साथ समाप्त होगा।

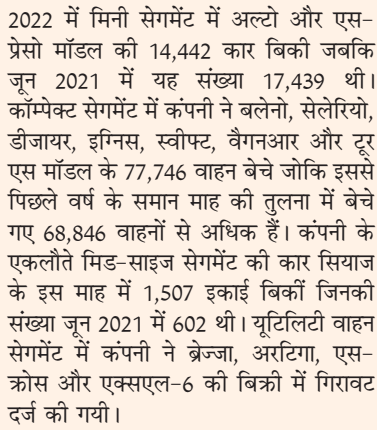
 सुरक्षा 	
सोना (प्रति दस ग्राम) स्टॅण्डर्ड	47,310
विदुर	47,320
गिन्नी (प्रति आठ ग्राम)	31,400
चांदी (प्रति किलो) टंच हाजिर	70,096
बायदा	70,183
चांदी सिक्का लिवाली	870
विकगाली	880

दाल-दलहन	
चना	4,600-4,700
दाल चना	5,700-5,850
मसूर काली	7,150-7,350
मलका मसूर	5400-6200
मूंग	8,200-8,500
मूंग दाल छिलका	6100-6700

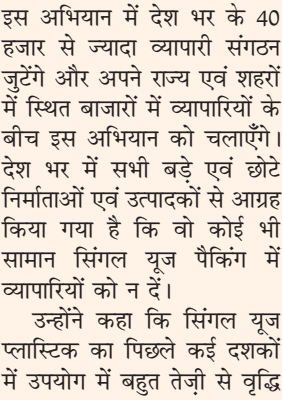


मारुति सुजुकी की बिक्री जून में 5.76 प्रतिशत बढ़ी

मारुति सुजुकी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कमी का वाहनों के निर्माण पर बहुत छोटा असर पड़ा है, खासतौर पर थ्रेल्ड मोडलों पर। कंपनी ने इसके प्रभाव को कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। कंपनी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून



देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद, कैट ने चलाया अभियान



रफ्तार कम होने से जून में पीएमआई नीचे आ गया। इस दौरान आपूर्तिकर्ताओं के प्रदर्शन में सुधार दिखा।

एसएआई ग्लोबल मार्केट इंटेल्जेंस का अर्थशास्त्री और सहायक निदेशिका पोल्यान्ना डी लीमा ने कहा कि भारतीय विनिर्माण उद्योग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में ठोस प्रदर्शन किया। भू-राजनैतिक चुनौतियों के बीच मुद्रास्फीति के दबाव, बढ़ती व्याज दरों, रुपये के मूल्य ह्रास के समक्ष इस क्षेत्र ने मजबूत प्रदर्शन किया।

कैट ने एक बयान में कहा कि देश भर में व्यापारियों ने समुचित अल्पियों के अभाव के बावजूद अपनी दुकानों पर प्लास्टिक थैलियों के स्थान पर कागज, जूट एवं कपड़े आदि के थैलों को सामान देना शुरू कर दिया है।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया की

हुई है और पर्याप्त विकल्पों के अभाव में एक दम से उपयोग बढ़ होना मुश्किल है किंतु फिर भी व्यापारियों ने अन्य उपलब्ध विकल्पों में ही अपने ग्राहकों का सामान देने का निश्चय किया है। देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक का व्यापार लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का होने का अनुमान है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन निगम, 2021 के अंतर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक के किसी भी सामान के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लग गया है। इस प्रकार से प्लास्टिक की छड़ियों के साथ ईयर बड, प्लास्टिक के झड़े, कैडी की छड़ें, आइसक्रीम की छड़ें, सजावट के लिए पॉलीस्टीलन (थर्मोकॉल), प्लास्टिक की प्लेट-कप, पैपिंग या पैकिंग फिल्म 100 माइक्रोन से कम आदि पर प्रतिबंध लग गया है।

चुनिंदा खाद्य तेलों और दालों
में नरमी, चीनी गुड़ गरम

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूरोपीय बाजार हरे निशान में जबकि एशियाई बाजार लाल निशान में दिखे। ब्रिटेन का एफटीएसई 0.17 प्रतिशत और जर्मनी का डैक्स 0.31 प्रतिशत

की बढ़त में रहा जबकि जापान का निष्प्रेषण 1.73 प्रतिशत, हांगकांग का हैंगसेंग 0.62 प्रतिशत और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.32 प्रतिशत की गिरावट में रहा।

बीएसई का सेंसेक्स 155 अंकों की गिरावट लेकर 53 हजार के स्तर से नीचे 52863.34 अंक पर खुला। सत्र के दौरान यह 53054.04 अंक के उच्चतम स्तर तक गया लेकिन बिकवाली के दबाव में यह 52094.25 अंक तक टूटा। अंत में यह पिछले दिवस के 53018.94 अंकों की तुलना में 0.21 प्रतिशत अर्थात् 111.01 अंक उत्तरकर 52907.93 अंक पर रहा। सेंसेक्स में शामिल 30 में 22 कंपनियाँ हरे निशान में जबकि आठ लाल निशान में दिखाई।

एनएसई का निफ्टी 77 अंकों की गिरावट लेकर 15703.70 अंक पर खुला। सत्र के दौरान यह 15793.95 अंक के उच्चतम और 15511.05 अंक के निचले अंक के बीच रहा। अंत में यह पिछले दिवस के 15780.25 अंकों की तुलना में 18.20 अंक अर्थात् 0.18 प्रतिशत टूटकर 15752.05 अंक पर रहा। निफ्टी में शामिल 50 कंपनियों में से 39 हरे निशान में जबकि 11 लाल निशान में दिखाई।

महंगा हो गया।

तेल-तिलहन : वैश्विक स्तर पर मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में पाम ऑयल का जुलाई वायदा 187 रिंगिट बढ़कर 487.5 रिंगिट प्रति टन हो गया। वहीं, अमेरिकी सोया तेल का जुलाई वायदा जुलाई 2012 0.12 सेंट की गिरावट लेकर 66.86 सेंट प्रति पौंड बोलो गया। इस दौरान सोया रिफाईंड 368 रुपये प्रति क्विंटल और वनस्पति 366 रुपये प्रति क्विंटल नरम पर गया जबकि मूंगफली, सरसों तेल, पॉम ऑयल और सूरजमुखी तेल में टिकाव रहा।

गुड़-चीनी : मीठे के बाजार में आवक घटने से तेजी रहा। चीनी 20 रुपये प्रति क्विंटल और गुड़ 100 रुपये प्रति क्विंटल

दाल-दलहन : दाल-दलहन के बाजार में गिरावट रही। इस दौरान चना, चना दाल 100 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग दाल 100 रुपये प्रति क्विंटल और अरहर दाल भी 100 रुपये प्रति क्विंटल टूट गयी। उड़द दाल और मसूर दाल में टिकाव रहा।

अनाज : अनाज मंडी में चावल और गेहूँ टिका रहा।

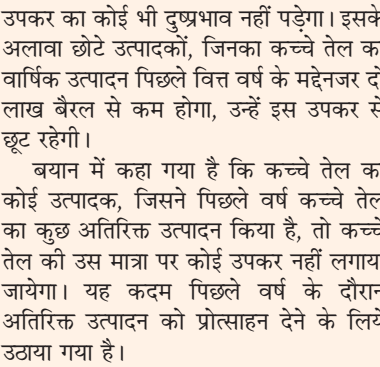
दाल-दलहन : चना 4400-4500, दाल चना 5400-5500, मसूर काली 8600-8700, मूंग दाल 8200-8300, उड़द दाल 9700-9800, अरहर दाल 8200-8300 रुपये प्रति क्विंटल रहे।

सीआईएबीसी के डायरेक्टर जनरल विनोद गिरी ने कहा कि कोई एफटीए या विदेशी कारोबारी अनुबंध यह जरूर सुनिश्चित करे कि सभी को एक समान अवसर मिलेंगे और सभी के लिए नियम एक होंगे। कोई भी पक्ष किसी नियम का दुरुपयोग अपने हित के लिए नहीं

करेगा। जब तक इंग्लैंड भारतीय व्हीसकी के लिए मिनिमम डेटरूस्डरिगन रिक्वारमेंट के नियम को नहीं हटाता है। उस समय तक इस क्षेत्र में लाभ केवल इंग्लैंड के पक्ष में रहेगा। इससे भारत को कोई फायदा नहीं होगा। भारत दुनिया में सबसे अधिक व्हीसकी उत्पादन करने वाला देश है। लेकिन इस नियम से उसकी व्हीसकी इंग्लैंड के बाजार में पहुंच ही नहीं पाएगी।

सीआरएबीसी ने कहा कि इंग्लैंड व्हीसकी के लिए तीन साल की मैन्युरिटी के नियम के सहारे हर नैतिक तरीके से अपनी व्हीसकी इंडस्ट्री को प्रतिस्पर्धा से बचाव देता है। भारत में सबसे अधिक व्हीसकी बनती है। लेकिन एक सच यह भी है कि हर साल भारत से निर्यात होने वाले 70 लाख व्हीसकी केशंस में से 10 हजार केशंस भी इंग्लैंड में नहीं पहुंच पाती हैं। इसका मुख्य कारण उसका तीन साल का नियम है। अगर उस नियम को तोना जाए तो इसके बनाने के दौरान उससे हवा में चले जाने वाले पदार्थ की वजह से भारतीय उत्पादकों को 30 प्रतिशत का नुकसान होता है। जिसकी वजह से वह इस नियम का अनुपालन कर ही नहीं सकते हैं।

कच्चे तेल पर 23,250 रुपये प्रति टन का उपकर लागू किया गया



पेट्रोल-डीजल के दाम
41वें दिन भी स्थिर

मुई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच शुक्रवार को पेट्रोल स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में नई बदलाव नहीं किया गया जिससे लगातार दो दिन ईंधन का दाम स्थिर रहे। तेल उपभोग करने वाली प्रमुख कंपनी भारत पेट्रोलियम के अनुसार दिल्ली में आज पेट्रोल का म 96.72 रुपये और डीजल का दाम 89.62 रुपये प्रति लीटर है, जबकि मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमशः 111.35 रुपये और 97.28 रुपये प्रति लीटर पर है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मूल्य वर्धित कर (वैट) और माल ढुलाई शुल्क के आधार पर बढ़ावों में अलग-अलग हैं। केंद्र सरकार ने मई अंतिम सप्ताह में आम आदमी को बड़ी राहत देने हुए पेट्रोल और डीजल पर उपाद शुल्क में छूट देकर आठ रुपये और छह रुपये प्रति लीटर ने कटौती करने की घोषणा की थी।

संपादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं लाठी, दृश्य तालिका, मुद्रक-सोनु डिजिटल गो-130, ओपनगा इन्फोटेक एडिया फेस-1, नई दिल्ली-110020, प्रकाशित कार्यालय :- फैक्ट इंडिया न्यूज, प्रिन्टिंग मैक, गिरिधर नं 5, एनएस गार्ड, निजामुद्दीन गेट, नई दिल्ली-110013, संपादक एवं तालिका, फोन/फैक्स नं. 919960445736, website: www.factindianews.com, factindianews@gmail.com, इसके समस्त विभागों ग्राहकों न्यायमूर्ति कार्यालयों एवं राजीव गिरीशों के लिए अंशिक नई दिल्ली न्यायमूर्ति में होगा

